

## रोजेन्स्टीन रोडान की विचारधारा<sup>ए</sup> (Big Push Theory) (Approach of Rosenstein Rodan)

रोजेन्स्टीन रोडान ने भी सन्तुलित विकास का समर्थन किया है, परन्तु वे चाहते हैं कि यह सन्तुलित विकास-पद्धति 'बड़े धक्के' (Big Push) के रूप में अपनाई जाए। 'बड़े धक्के' के सिद्धान्त ('Theory of Big Push') के अनुसार स्थिर अर्थ-व्यवस्था (Stagnant Economy) की प्रारम्भिक जड़ता को समाप्त करने के लिए और इसे उत्पादन तथा आय के उच्च स्तरों की ओर बढ़ने के लिए न्यूनतम प्रयत्न या 'बड़े धक्के' (Big Push) की आवश्यकता है। यह बड़ा धक्का तब होता है, जब एक साथ ही विभिन्न प्रकार की कोई पूरक परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाए।

रोडान के मतानुसार, "अद्वा-विकसित अर्थवा अल्प-विकसित देशों में आर्थिक व सामाजिक ऊपरी सुविधाओं (Economic and Social overheads) की नितान्त कमी होती है जिनकी पूर्ति करने की न तो निजी साहसियों में क्षमता होती है और न ही इच्छा।" अतः राज्य को चाहिए कि वह इन ऊपरी सुविधाओं (Social and Economic overheads) अर्थात् यातायात, संचार, शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, ट्रेनिंग आदि में अधिक मात्रा में धन लगाए और इस प्रकार निजी विनियोजकों तथा श्रीद्योगीकरण के इच्छुक लोगों को उद्योग खोलने की प्रेरणाएँ और सुविधाएँ प्रदान करे। प्रो. रोडान के अनुसार, अद्वा-विकसित देशों में धीरे-धीरे विकास करने की पद्धति अपनानी ठीक नहीं है। इन देशों में वास्तविक विकास तो केवल 'बड़े धक्के' (Big Push) से ही सम्भव है क्योंकि तभी हम 'उत्पादन की बाह्य मितव्यता' अर्थवा उत्पत्ति वृद्धि के नियम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

"यदि विकास की किसी भी आयोजना में सफल होता है तो इसके लिए एक न्यूनतम मात्रा में विनियोजन आवश्यक होगा। किसी देश को स्वयं स्फूर्ति विकास की स्थिति में पहुँचने के लिए प्रयत्न करना भूमि से हवाई जहाज के उठने के समान है। हवाई जहाज को नभ में उड़ान के लिए एक निश्चित गति पकड़ना आवश्यक है। धीरे-धीरे बढ़ने से काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार विकास कार्यक्रम को

सफल बनाने और अर्थ-व्यवस्था को स्वयं स्फूर्त दशा में पहुँचने के लिए बड़े धक्के के रूप से एक निश्चित मात्रा में समस्त क्षेत्रों में विनियोजन अनिवार्य है।”

“विकास की बाधाओं को लगने के लिए बड़ा धक्का ही आवश्यक है। एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में उत्साह और कार्य से काम नहीं चल सकता। छोटे-छोटे और यदा-कदा किए जाने वाले प्रयत्नों से विकास सम्भव नहीं हो सकता। विकास का वातावरण तभी उत्पन्न होता है जब एक न्यूनतम मात्रा का विनियोजन एक न्यूनतम गति से किया जाए।”

प्रो. रोडान के ‘बड़े धक्के के सिद्धान्त’ के पक्ष में प्रमुख तर्क अर्द्ध-विकसित देशों में बाह्य मितव्ययताओं के अभाव पर आधारित है। बाह्य मितव्ययताओं का आशय उन लाभों से है जो समस्त अर्थ-व्यवस्था या कुछ क्रियाओं या उपकरणों को मिलते हैं किन्तु जो विनियोक्ता इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप में कोई प्रत्याय (Returns) नहीं देते हैं। पूर्ति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाह्य मितव्ययताएँ यातायात, शक्ति आदि के रूप में सामाजिक ऊपरी सुविधाएँ (Social overhead facilities) हैं, जो अन्य क्षेत्रों में भी विनियोग के अवसर बढ़ाते हैं। रोजेन्स्टीन रोडान ने निम्न-लिखित तीन प्रकार से बाह्य मितव्ययताओं और अविभाज्यताओं (Indivisibilities) में भेद किया है—

(i) उत्पादन-कार्य में विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूँजी की पूर्ति में अविभाज्यता (Indivisibility of production function, specially in the supply of social overhead capital).

(ii) माँग की अविभाज्यता या माँग की पूरक प्रकृति (Indivisibility of demand or the complementary character of demand).

(iii) बचत की पूर्ति में अविभाज्यता (Indivisibility in the supply of savings).

सामाजिक ऊपरी पूँजी की पूर्ति की अविभाज्यता स्वाभाविक है, क्योंकि इसका न्यूनतम आकार आवश्यक रूप से ही बड़ा (Necessarily large minimum size) होता है। उदाहरणार्थ, आधी रेल लाइन के निर्माण से कोई लाभ नहीं होगा, अतः पूरी रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा में विनियोग करना अनिवार्य है। साथ ही, इस प्रकार का विनियोग प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं के पूर्व होना चाहिए। नियति के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विनियोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि खेतों से बन्दरगाहों पर कृषि-उपज को पहुँचाने के लिए सड़क का निर्माण नहीं कर दिया जाता। रोजेन्स्टीन रोडान का माँग की अविभाज्यता का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि एकाकी विनियोग परियोजना को बाजार की कमी की भारी जोखिम को उठाना पड़ सकता है। इसके विपरीत, यदि कई पूरक परियोजनाओं को एक साथ प्रारम्भ किया जाता है तो वे एक-दूसरे के लिए बाजार प्रस्तुत कर देते हैं और उनके असफल होने की सम्भावना नहीं रहती है। रोजेन्स्टीन रोडान इस बात को एक जूते के कारखाने के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते

है। मानलो कि एक स्थेतिक और बन्द अर्थ-व्यवस्था में एक जूतों का कारखाना स्थापित किया जाता है जिसमें 100 श्रमिकों को जो पहले अर्द्ध-नियोजित थे, काम पर लगाया जाता है। उनको दी जाने वाली मजदूरी उनकी आय होगी किन्तु इसका क्योंकि अतिरिक्त क्रय-शक्ति का कोई साधन नहीं है और निर्यात की भी कोई असफल हो जाएगा। किन्तु स्थिति उस समय एकदम भिन्न और अविक अच्छी होगी यदि एक नहीं अपितु 10,000 पहले के अर्द्ध-नियोजित श्रमिकों को काम पर लगाने वाले 100 कृषि और औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए जाएँ जिनमें अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्र की तुलना में उत्पादकता के उच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ को खरीदने के काम में लाई जा सकेगी और कुल विनियोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी।

‘बड़े धक्के के सिद्धान्त’ के सन्दर्भ में तीसरी अर्थात् ‘बचत की पूर्ति’ की अविभाज्यता की धारणा का उदय इस बात से होता कि विशाल न्यूनतम विनियोग कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए ऊँची न्यूनतम बचत अनिवार्य है। रोजेन्स्टीन रोडान के मतानुसार “आय के नीचे स्तर वाली अर्द्ध-विकसित अवस्थाओं में बचत ऊँची दरों को प्राप्त करने का एक मात्र तरीका विनियोगों में वृद्धि ही है जिसे इन देशों में यहाँ के अविकसित और अप्रयुक्त जन-शक्ति तथा अन्य साधनों को गतिशील बना कर ही प्राप्त किया जा सकता है।”

इस प्रकार उपरोक्त अविभाज्यताओं का पूरा लाभ उठाने और बाह्य-मितव्ययताओं से लाभान्वित होने के लिए विशाल मात्रा में विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी विनियोग करना चाहिए, अर्थात् अर्थ-व्यवस्था को ‘बड़ा धक्का’ विकास की ओर लगाना चाहिए। प्रो. नर्कसे ने भी रोजेन्स्टीन रोडान की उपरोक्त अविभाज्यताओं के आधार पर ही सन्तुलित विकास की पद्धति का समर्थन किया है। बड़े धक्के के सिद्धान्त में संस्थागत परिवर्तन पर भी जोर दिया गया है। किन्तु इस सिद्धान्त को भी पूर्ण नहीं माना गया है। अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के कार्यक्रम में ‘बड़ा धक्का’ (Big push) लगना बड़ा कठिन है क्योंकि इन देशों के साधन अत्यल्प होते हैं। इसके अतिरिक्त सन्तुलित विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध जो आलोचनाएँ की जाती हैं वे सामान्यतया इस सिद्धान्त पर भी लागू होती हैं।